जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के विमोचन के अवसर पर प्रधानमंत्री का भाषण

(दिनांक 30 जून, 2008)

जलवायु परितर्वन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना की औपचारिक शुरूआत के अवसर पर आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस शुरूआत के साथ सरकार ने इस वर्ष के मध्य तक राष्ट्रीय योजना घोषित करने की अपनी औपचारिक प्रतिबद्धता परिपूर्ण कर ली है। यह जलवायु परितर्वन की चुनौतियों से निपटने में हमारी राष्ट्रीय ऊर्जाओं एवं संसाधनों को एकत्रित करने में हमारे द्वारा दिये जाने वाले अपार महत्व को प्रदर्शित करता है। एक सतर्क दीर्घ अवधि रणनीति के बिना जलवायु परिवर्तन हमारे विकास के प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसके कारण हमारे लोगों की आजीविका और जीवन के मानदंडों पर विपरीत परिणाम होंगे। उस पर्यावरण में जिसमें वे रहते हैं और कार्य करते हैं और उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं देखरेख पर। यह एक ऐसी चुनौती भी है जिसने वर्तमान एवं भविष्य दोनों पीढियों के हितों को घेर रखा है। हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ऐसी दुनिया सौंपे जो सुरक्षित, स्वच्छ एवं उत्पादक हो और जो नीचे समुद्र की अनंतता के साथ, बर्फ से आच्छादित पर्वतों की उत्तंगता के साथ, विस्तृत वनों के हरित विस्तार के साथ और हमारी प्राचीन नदियों की स्निग्ध धाराओं के साथ मानव कल्पना को प्रोत्साहन देती रहेगी । यह एक ऐसी दुनिया है जिसे हम विश्वास के साथ रखते हैं, यह एक ऐसी दुनिया है जिसने अनगिनत पीढियों के लिए जीवन का निर्माण एवं पालन किया है। आज, मनुष्य की आर्थिक गतिविधि के माध्यम से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के जमा होने के कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह के लिए खतरा बन गया है । जीवन का निर्वाह करने वाले दुर्बल पारिस्थितिकी जो इस संसार को एक साथ मिलाकर रखती है के भयानक विघटन की एक वास्तविक संभावना है । विज्ञान इस औपचारिक मूल्यांकन पर अब बिल्कुल स्पष्ट है ।

भारत की एक सभ्यतागत परंपरा है जो प्रकृति को पालन का एक स्रोत मानती है न कि ऐसी अंधकारमय शक्ति जिस पर विजय प्राप्त की जाए और मानव उपभोगों के लिए इसका दोहन किया जाए । साझी किस्मत के कोमल धागे को, जो ब्रह्माण्ड को एक साथ रखते हैं, मान्यता देते हुए प्रकृति को एक साथ रखते हैं, प्रकृति के साथ सौहाद्रपूर्ण तरीके से जीवन यापन की विचारधारा को हमारी संस्कृति में ऊंचा स्थान दिया गया है । समय आ गया है कि हम प्राचीन परंपराओं से सीखें और पारिस्थितिकी निर्वाहयोग्य विकास के पथ पर भारत और इसके करोड़ों लोगों को चलने के लिए मार्ग प्रशस्त करें । हमारे लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एवं सब तरफ फैली गरीबी के कलंक को धोने का अधिकार है । इसके लिए हमें तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता है। लेकिन मैं यह भी विश्वास करता हूं कि पारिस्थितिकी निर्वाह योग्य विकास का हमारे विकास लक्ष्यों के साथ विरोध की आवश्यकता नहीं है । वास्तव में, हमें विकास का एक विस्तृत दृष्टिकोण रखना चाहिए । इसमें सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के परिमाणात्मक जोड़ ही नहीं होंगे बल्कि जीवन की गुणवत्ता को शामिल किया जाना है । हमारे लोग उच्च जीवन स्तर चाहते हैं लेकिन वे स्वच्छ पेय जल, सांस लेने के लिए ताजी हवा और भ्रमण के लिए हरी धरती भी चाहते हैं । हमने आज जिस राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा की है, उसमें निर्वाह योग्य विकास के भारत के दृष्टिकोण और उन कदमों को शामिल किया गया है, जो हमें इसे प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने के लिए उठाना चाहिए ।

इस योजना में बहुत व्यापक एवं विस्तृत उपायों को शामिल किया गया है । यह योजना ऐसी ही होनी चाहिए क्योंकि हम जिस चुनौती का सामना करते हैं वह जटिल एवं परस्पर विरोधी प्रकृति की है । इसके बावजूद हमने आठ राष्ट्रीय मिशनों पर अपनी राष्ट्रीय ऊर्जाओं को केन्द्रित करने का निर्णय लिया है जो निर्वाहयोग्य विकास के लिए हमारी रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में आगे बढ़ायी जाएंगी । इनमें सौर ऊर्जा, अभिवर्द्धित ऊर्जा कुशलता, निर्वाह योग्य आवास, जल संरक्षण , हिमालयी पारिस्थितिकी के निर्वाह, हरित भारत के निर्माण, निर्वाह योग्य कृषि और जलवायु परिवर्तन के लिए एक सामरिक ज्ञान प्लेटफार्म स्थापित करने पर राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया गया है । हमारा दृष्टिकोण है भारत के आर्थिक विकास को उर्जा कुशल बनाना । कुछ समय के बाद हम लोगों को जीवाश्म इपधन पर आधारित आर्थिक गतिविधि को धीरे-धीरे गैर जीवाश्म इपधन पर आधारित बनाना होगा और ऊर्जा के गैर अक्षय एवं खत्म होते स्रोतों से निर्भरता को ऊर्जा के रूप में बदलना होगा । इस रणनीति में सूर्य केन्द्र स्थान पर आता है जहां इसे सभी ऊर्जा के मूल स्रोत होने के कारण होना चाहिए । हम हमारे वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रबंधन प्रतिभा को पर्याप्त संसाधनों से एकत्र करेंगे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देने के लिए अपार ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का विकास कर सकें और हमारे लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें।इस प्रयास में हमारी सफलता भारत का चेहरा बदल देगी। यह विश्वभर के लोगों की किस्मत बदलने में भारत को समर्थ बनाएगी ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसे एवं अन्य महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास बुद्धि, रचनात्मकता और हमारे लोगों का उद्यम है। इन संपदाओं को आकर्षित करने के लिए इस योजना **का लक्ष्य** सरकार से भी आगे जाने का है। राष्ट्रीय कार्य योजना को आगे बढ़ाने में, हम सचेत हैं कि हम तेजी से बदलते और अनिश्चितता के युग में रहते हैं । इस प्रकार यह योजना स्थिरता नहीं है । इसका आशय बदलती परिस्थितियों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकासीय बदलाव के मद्देनजर तैयारी करना और बदलाव लाना है । जो वैश्विक प्रणाली में फिलहाल बहुपक्षीय वार्ताओं के जरिए किया जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन वैश्विक चुनौती है इससे सिर्फ वैश्विक, सहयोगात्मक और सहकारी प्रयासों के जरिए ही सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है । भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जिम्मेदार सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाने तथा अपना योगदान **देने** के लिए तैयार है । हम जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत बहुपक्षीय वार्ताओं में ऐसा पहले ही कर रहे हैं । हम जिन नतीजों का इंतजार कर रहे हैं वे प्रभावशाली होने चाहिए । यह उचित एवं एकसमान होना चाहिए । इस ग्रह के प्रत्येक नागरिक की इस ग्रह के वायुमंडल में समान भागीदारी होनी चाहिए । इसलिए प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का दीर्घावधि रूपान्तरण जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रभाव का एकमात्र एकसमान आधार है । इस बीच, मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि अपने विकासात्मक महत्व के बावजूद हमारा प्रतिव्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन विकसित औद्योगिक देशों के प्रतिव्यक्ति जीएचजी उत्र्सन से अधिक नहीं होगा । **हमारी यह घोषणा** पर्याप्त साक्ष्य **है। यदि किसी बात की जरूरत है तो वह है-** उद्देश्यों की ईमानदारी **और** जिम्मेदारी की भावना **ताकि हम** इस वैश्विक कार्य को **हाथ में ले सकें**।

राष्ट्रीय कार्ययोजना अपनी उपस्थिति के लिए अनेक लोगों की बुद्धि, विशेषज्ञता और समर्पण की आभारी है । मुझे जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद के सभी सदस्यों को धन्यवाद

देना चाहिए तथा खासतौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल, सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डा0 चिदम्बरम और जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्री श्याम सरन को जिन्होंने योजना के अंतिम मसौदे का अवलोकन किया । मेरा अपना मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मंत्रालय के राज्यमंत्री श्री मीणा के नेतृत्व में हम सबके विचार-विमर्श में प्रारंभिक भूमिका निभाई है । मुझे ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा योजना आयोग की भी प्रशंसा करनी चाहिए । यह योजना राष्ट्रीय बहस का विषय बननी चाहिए । अब तक की तुलना में, बेहद व्यापक विचार विमर्श के जरिए यह योजना तैयार और संशोधित की जाएगी । सरकार, अपने स्तर पर विभिन्न राष्ट्रीय मिशन की तेजी से स्थापना करने का इरादा रखती है तथा विशिष्ट परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विस्तृत योजना बनाना चाहती है । हम अपने राष्ट्रीय प्रयास में सहायता और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का स्वागत करेंगे ।

मैं न सिर्फ भारत के लोगों परन्तु पूरे विश्व के लोगों के लिए महात्मा गांधी के दूरदर्शी संदेश को दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि पृथ्वी के पास सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं परन्तु उनके लालच को पूरा करने के लिए वे कभी पर्याप्त नहीं होंगे । यही वह भावना है जो टिकाऊ विकास की किसी भी रणनीति की बुनियाद में होनी चाहिए ।

***